

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा**  
**पीठासीन अधिकारी: श्री मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस.**

प्रकरण संख्या : 37/2023 (अपील)

**उनवान**

बाबूलाल पुत्र गंगाराम जाति बैरवा निवासी गडावद तहसील पीपल्दा  
जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

**बनाम**

राजस्थान राज्य जर्गे तहसीलदार, पीपल्दा तहसील पीपल्दा  
जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :- 1. श्री जाकिर हुसैन (अभिभाषक अपीलाण्ट)  
2. पेरोकार सरकार (पेरोकार सरकार रेस्पो0 की ओर से)

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956**  
**बनाराजगी आदेश दिनांक 10.03.2022 मि0नं0 915/2022**  
**न्यायालय तहसीलदार, पीपल्दा, जिला कोटा**

**निर्णय दिनांक : 06.06.2024**

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।
2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।
3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
4. अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का अपील बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को ग्राम गडावद की आराजी ख0न0 19 रकबा 0.50 हैक्टर किस्म चारागाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना मानकर बेदखल करने का तथा 50 गुना शास्ती आरोपित करने का तथा 90 दिन की सिविल कारावास की सजा से दंडित करने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सूचना दिये बिना ही केवल पटवारी हल्का की एक पक्षीय रिपोर्ट का आधार बनाकर अपीलाण्ट को अपनी जवाब देही करने का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित कर दिया। पत्रावली पर ऐसा कई दस्तावेज साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे की अपीलाण्ट द्वारा उक्त आराजी पर पश्चावती अतिक्रमण किया जाना साबित हो। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर पश्चावती अतिक्रमण नहीं किया है और ना ही पूर्व में अपीलाण्ट को उक्त आराजी से बेदखल किया गया है। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर से अपना कब्जा छोड दिया है, और तावान की राशि जमा करवा दी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

**अति. जिला कलेक्टर**  
**कोटा**

5. रेस्पोजेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अभिभाषक का बहस में कथन है कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने पर उसे पूर्व में बेदखल किया गया है। उसके बावजूद अप्रार्थी अपीलान्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट अप्रार्थी का बहस अपील में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को ग्राम गडावद की आराजी ख0न0 19 रकबा 0.50 हैक्टर किस्म चारागाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना मानकर बेदखल करने का तथा 50 गुना शास्ती आरोपित करने का तथा 90 दिन की सिविल कारावास की सजा से दंडित करने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही केवल पटवारी हल्का की एक पक्षीय रिपोर्ट का आधार बनाकर अपीलान्ट को अपनी जवाब देही करने का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित कर दिया। पत्रावली पर ऐसा कई दस्तावेज साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे की अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना साबित हो। अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं किया है और ना ही पूर्व में अपीलान्ट को उक्त आराजी से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर से अपना कब्जा छोड़ दिया है, और तावान की राशि जमा करवा दी है। रेस्पोजेण्ट अप्रार्थी की ओर से उपस्थित राजकीय अभिभाषक का बहस में कथन रहा है कि "अपीलान्ट द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने पर उसे पूर्व में बेदखल किया गया है। इसके बावजूद अप्रार्थी अपीलान्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है।" उभय पक्ष की ओर से बहस में किये गये उक्त कथन, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुऐ अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्ट सशर्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट अप्रार्थी को वाके ग्राम गडावद स्थित आराजी खसरा नम्बर 19 रकबा 0.50 हैक्टर पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के आरोप में दिये गये सिविल कारावास की सजा के आदेश को दो माह के लिये इस शर्त के साथ स्थगित किया जाता है कि इस निर्णय की दिनांक से एक माह के अन्दर अपीलान्ट अप्रार्थी स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा उपरोक्त अतिक्रमणित आराजी से वास्तविक रूप से मौके से कब्जा हटा लिया गया है, एवं भविष्य में पुनः अतिक्रमण नहीं करेगा। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलान्ट अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त शपथ पत्र की मौके पर से वास्तविक रूप से कब्जा हटा लेने की पुष्टि सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक से करावे। अपीलान्ट अप्रार्थी का उपरोक्त अतिक्रमणित आराजी पर से मौके पर से वास्तविक रूप से कब्जा हटा लेने बाबत प्रस्तुत उक्त शपथ पत्र सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक से पुष्टि में सही प्रमाणित पाये जाने पर निर्णय जैर अपील से अपीलान्ट अप्रार्थी को दी गई सजा निरस्त होगी, अन्यथा अपीलान्ट अप्रार्थी को उक्त शर्त के उल्लंघन पर इस निर्णय की दिनांक से दो माह के लिये स्थगित की गई सिविल कारावास की सजा का आदेश पुनः प्रभावी होगा। अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली में आदेशिका लिखते हुऐ विधि के अनुरूप नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लावे। अधीनस्थ न्यायालय का शेष आदेश यथावत रहेगा।

8. निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी)  
अतिरिक्त न्यायालय अधिकारी  
कोटा जिला कोटा